

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2216/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट प्रथम, डूंगरपुर वृत्त डूंगरपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ब्रह्म प्रकाश मोदी, जयपुर

द्वारा गोपाल सिंह, लेखाकार

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री दिनेश कुमार

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 31.07.2014

निर्णय

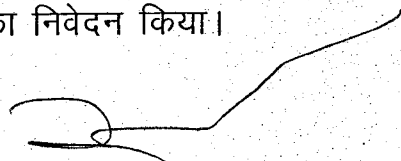
यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, डूंगरपुर वृत्त डूंगरपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 34/अपील्स-चतुर्थ/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.03.2009 को सावली से झालावाड जाते समय वाहन संख्या जीजे-6टी.टी. 5852 को रतनपुर पर रूकवाया तथ परिवहनित माल के दस्तावेज मांगे गये। इस पर श्री भूपत सिंह वाहन चालक एवं माल प्रभारी ने जी आर नम्बर 1119 दिनांक 3.3.2009 एवं इनवाइस नम्बर 8001030 क्रमांक 292613 दिनांक 3.3.2009 एवं हिन्दुस्तान कोलास लिमिटेड की टेस्ट रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग वैट-47 होना आवश्यक माना है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों के साथ वैट-47 नहीं होने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण करने हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में बताया गया कि दिनांक 27.2.2009 को विभाग द्वारा अचानक वैट-47 फार्म की अनिवार्यता लागू कर दी गयी है, जिसकी जानकारी नहीं होने से वैट-47 संलग्न नहीं किया गया है अब वैट-47 नम्बर 3904726 जवाब के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए जवाब के साथ वैट-47 संलग्न करना बाद की सोच मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) सपठित नियम 53 के अनुसार वैट-47 का होना आवश्यक मानते हुए माल की कीमत रु. 4,12,166/- पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,23,650/- आरोपित कर आदेश दिनांक 7.3.2009 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 7.3.2009 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2010 पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2010 से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित किया जा रहे माल साथ वैट-47 नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैट-47 होना आज्ञापक है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ वैट-47 नहीं होने कारण अधिनियम की धारा 76(2)का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,23,650/-आरोपित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2010 पारित किया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

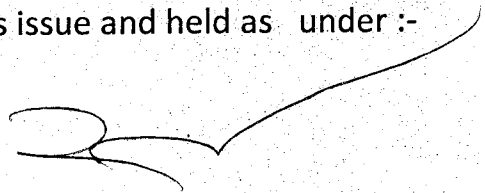
प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग वाहन के साथ समस्त वांछित दस्तावेज मौजूद थे, जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर, उसके ना होने के कारणों का खुलासा करते हुए वैट-47 जवाब के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था इसलिए शास्ति आरोपण अविधिक है। उनका कथन है कि उक्त माल परिवहन करने में कोई दोषी मनोभाव नहीं था। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए कथन किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। उनका यह भी कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी पी मेटल्स (124 एस टी सी 611) में पारित निर्णय को उद्धृत कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।



उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 04.03.2009 को सावली से झालावाड जाते समय वाहन संख्या जीजे-6टी.टी. 5852 को रतनपुर पर रूकवाया तथ परिवहनित माल के दस्तावेज मांगे गये। इस पर श्री भूपत सिंह वाहन चालक एवं माल प्रभारी ने जी आर नम्बर 1119 दिनांक 3.3.2009 एवं इनवाईस नम्बर 8001030 क्रमांक 292613 दिनांक 3.3.2009 एवं हिन्दुस्तान कोलास लिमिटेड की टेस्ट रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग वैट-47 होना आवश्यक माना है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों के साथ वैट-47 नहीं होने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण करने हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में बताया गयाकि दिनांक 27.2.2009 को विभाग द्वारा अचानक वैट-47 फार्म की अनिवार्यता लागू कर दी गयी है, जिसकी जानकारी नहीं होने से वैट-47 संलग्न नहीं किया गया है अब वैट-47 नम्बर 3904726 जवाब के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए जवाब के साथ वैट-47 संलग्न करना बाद की सोच मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) सपठित नियम 53 के अनुसार वैट-47का होना आवश्यकत मानते हुए माल की कीमत रु. 4,12,166/- पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,23,650/-आरोपित की है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ वैट-47 नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस दिये जाने पर वैट-47 नहीं होने के कारणों का खुलासा करते हुए जवाब के साथ वैट-47 संख्या 3904726 प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच दस्तावेजों के साथ वैट-47 नहीं होना सद्भाविक (**bonafide**) भूल है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उस सन्दर्भ में उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-



The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

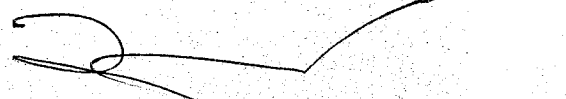
उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाड़ा के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2010



-5-अपील संख्या 2216/2010/जयपुर

के, यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य